P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-2* October- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

कृषि क्षेत्र के विकास में बैंकों की भूमिका (बडवानी जिले के संदर्भ में)

Rols of Banks in Development of Agriculture Sector (With Reference to Barwani)

Paper Submission: 15/10/2020, Date of Acceptance: 26/10/2020, Date of Publication: 27/10/2020

आशीराम सस्त्या
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
देवी महिला वि. वि.
इन्दौर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

वित्त की आवश्यकता उन क्षेत्रों में होती है, जहां किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं विपणन का कार्य किया जाता है अतः इस क्षेत्र में उत्पादन एवं विपणन संबंधी क्रियाओं को संपादित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मशीन को चलाने के लिए तेल तथा मानव शरीर को चलाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार कृषि व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त के अभाव में न तो कोई व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित या विकसित किया जा सकता है। इसी कारण से वित्त को किसी भी व्यवसाय की मूल क्रियाओं का आधार स्तम्भ माना जाता है। वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के दौर में विकास प्रक्रिया को अधिक सुदृढ पारदर्शी एवं जनउपयोगी बनाने की दिशा में बैंकिंग तंत्र द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहें है। गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास हेतु जिलें में कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण आदिवासी कृषकों को मिला है जिससे उनकी कृषि आय में वृद्वि हुई है और उनका सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनैतिक जीवन में उन्नति हुई है।

Finance is required in those areas where some form of economic activity is edited. Production and marketing work is done in the agriculture sector, so finance is required to perform production and marketing related activities in this area. Just as oil is needed to run a machine and blood is needed to run the human body, in the same way finance is needed in agriculture business. In the absence of finance, neither a business can be established nor can it be operated or developed. For this reason, finance is considered the pillar of the basic activities of any business. In the era of globalization and economic liberalization, continuous efforts are being made by the banking system to make the development process more robust, transparent and useful. Several schemes are being operated in the districts for poverty alleviation and rural development. Rural tribal farmers have benefited from these schemes, which have increased their agricultural income and improved their social, economic and political life.

मुख्य शब्द : प्राथमिक क्षेत्र, वित्त, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय आय, वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक एंव द्वितीयक संमक ।

Primary Sector, Finance, Kisan Credit Card, National Income, Globalization and Economic Liberalization, Poverty Alleviation, Primary and Secondary Composite.

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग अपनी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है। कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो देश के लगभग 57 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 73 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। गरीबी दूर करने, आमदनी और रोजगार के अवसर बढाने, खाद्य सुरक्षा और उद्योग तथा सेवाओं के लिए घरेलू बाजार को बनाए रखने के लिए कृषि पर ध्यान देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करना आवश्यक है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी कृषि क्षेत्र के विकास हेतु कई योजनाओं का सफल संचालन एवं क्रियान्वयन कर कृषि विकास दर का नया इतिहास रच

दिया है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किये गए वर्ष 2013–14 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार म. प्र की कृषि विकास दर 24.99 प्रतिशत रही। वर्ष 2012–13 में कृषि विकास दर 20.16 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष 2011–12 में 19.85 प्रतिशत रही थी ।

मध्य प्रदेश सरकार को लगातार तीसरी बार कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्वि हेतु कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना तथा बैंकों द्वारा वित्तीय पोषण से इस क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। इसी महत्व को ध्यान में रखकर भारतीय बैकों को ग्रामीण क्षेत्र से जोडा गया और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण आदिवासियों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएं कियान्वित की गयी परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने तथा कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में बडा योगदान मिला।

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध पत्र में कृषि क्षेत्र के विकास मे बैंकों की भूमिका (बडवानी जिले के संदर्भ में) को निम्न उद्देश्यों से जानने का प्रयास किया गया है।

शोध पत्र के उद्देश्य

1. बैंकों द्वारा वितरित कृषि ऋण का वर्षवार तुलनात्मक अध्ययन कर कृषि क्षेत्र के विकास में व्यावसायिक बैंकों की भूमिका का अध्ययन करना।
2. किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत वितरित ऋण एवं ऋण के उपयोग का अध्ययन एवं उसकी समीक्षा करना।
3. जिले की कृषि क्षेत्र की समस्याएं एवं कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहें प्रयासों का अध्ययन करना एवं कृषि समस्याओं को दूर करने हेतु सुझाव देना।

साहित्यावलोकन

लघु शोध प्रबंध के शीर्षक "बडवानी जिले में चयनित व्याससायिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त से ग्रामीण आदिवासियों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन– एक मूल्यांकन" बडवानी जिले के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जिसमें जिले में कार्यरत पांच प्रमुख बैंकों का चयन कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाकर कृषि क्षेत्र के निरंतर घटते योगदान को बढाने हेतु बैंको द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास हेतु दी जा रही सुविधाओं तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किये जा रहें प्रयासों का अध्ययन कर ग्रामीण आदिवासियों के विकास हेतु आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास पर जोर दिया गया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र बडवानी जिले के विशेष संदर्भ में है। जिले में कार्यरत व्यावसायिक बैकों मे से पांच प्रमुख बैकों जिसमें जिले का अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर, भारतीय स्टैट बैंक, नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का चयन किया गया है। शोध पत्र में प्राथमिक व द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। जिले में कार्यरत प्रमुख पांच बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास में बैंकों के योगदान के तुलनात्मक अध्ययन हेतु बैंक द्वारा लक्षित ऋण एवं वितरित ऋण का वर्षवार तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बैंकों के योगदान का अध्ययन किया गया है तथा किस प्रकार संस्थागत ऋण की पूर्तिकर देश की जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र के योगदान को बढाया जा सकता है। उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिले की पांच प्रमुख बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत वितरित ऋण एवं कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

तालिका 1.1

किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत वितरित ऋण का विवरण (राशि हजारों में)

क्रमांक	बैंक का नाम	31 दिसम्बर 2006		31 दिसम्बर 2005	
		खाता संख्या	राशि	खाता संख्या	राशि
1	बैंक ऑफ इण्डिया	691	67906	889	112436
2	स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर	262	11652	191	11190
3	भारतीय स्टैट बैंक	474	54389	111	45706
4	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	468	21118	649	123902
5	कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	000	000	06	110
कुल		**1895**	**155135**	**1846**	**293344**

स्त्रोतः– जिले का अग्रणी बैंक बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित।

तालिका 1.1 में किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्ग वितरित ऋण का विवरण दिया गया है। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते है–

1. जिले का अग्रणी बैंक बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा वर्ष 2005 में कुल 889 खातो से 112436 (हजार रूपये) ऋण राशि का वितरण किया गया है जो वर्ष 2006 की तुलना में कुल 691 खातों से 67906 (हजार रूपये) वितरित ऋण राशि से 39.60 प्रतिशत अधिक है।
2. स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर द्वारा वर्ष 2005 में कुल 191 खातो से 11190 (हजार रूपये) ऋण राशि का वितरण किया गया है जो वर्ष 2006 की तुलना में कुल 262 खातों से 11952 (हजार रूपये) वितरित ऋण राशि से 4.12 प्रतिशत अधिक है।
3. भारतीय स्टैट बैंक द्वारा वर्ष 2005 में कुल 111 खातो से 45706 (हजार रूपये) ऋण राशि का वितरण किया गया है जो वर्ष 2006 की तुलना में कुल 474 खातो से 54389 (हजार रूपये) वितरित ऋण राशि से 18.99 प्रतिशत अधिक है।
4. नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक द्वारा वर्ष 2005 में कुल 649 खातो से 123902 (हजार रूपये) ऋण राशि का वितरण किया गया है जो वर्ष 2006 की तुलना में

कुल 468 खातो से 21188 (हजार रूपये) वितरित ऋण राशि से 48.48 प्रतिशत अधिक है।

उपर्युक्त समंकों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बैकों द्वारा प्रतिवर्ष इस योजना के अन्तर्गत ऋणों के वितरण में प्रतिवर्ष वृद्वि की गयी है तथा औसत से अधिक मात्रा में ऋणों का वितरण किया गया है।

तालिका 1.2

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण एवं कुल अग्रिम का प्राथमिकता क्षेत्र प्रतिशत (राशि हजारों में)

स. क्र.	बैंक का नाम	वर्ष									
		2002		2003		2004		2005		2006	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	बैंक ऑफ इण्डिया	431705	81	427647	73	521844	77	779895	91	821017	84
2	स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर	414471	88	871525	94	1147824	92	1770796	94	1869278	92
3	भारतीय स्टैट बैंक	23303	62	36288	68	56209	82	149525	85	211314	90
4	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	125343	80	157519	85	174296	82	242728	86	263367	84
5	कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	34671	46	13065	14	102742	96	124963	100	128892	97
कुल		1029493		1506044		2002915		3067907		3293868	

स्रोतः– जिले का अग्रणी बैंक बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित।

तालिका 1.2 में कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण एवं कुल अग्रिम का प्राथमिकता क्षेत्र प्रतिशत को दर्शाया गया है। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि–

1. पांचो बैंकों द्वारा वितरित किये गए ऋणों का तुलनात्मक विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002 में कृषि क्षेत्र हेतु सबसे अधिक ऋण स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर द्वारा दिया गया। इसके पश्चात् स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा तथा नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक द्वारा दिया गया। इस प्रकार वर्ष 2002 में कुल 1029493 (हजार) राशि वितरित की गयी।
2. वर्ष 2003 में कृषि क्षेत्र हेतु सबसे अधिक ऋण स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर द्वारा दिया गया । इसके पश्चात् नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक द्वारा तथा बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दिया गया। इस प्रकार वर्ष 2003 में कुल 22928 खातो से कुल 1506044 (हजार) राशि वितरित की गयी।
3. वर्ष 2004 में कृषि क्षेत्र हेतु सबसे अधिक ऋण कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिया गया। इसके पश्चात् स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर द्वारा तथा नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक द्वारा दिया गया। इस प्रकार वर्ष 2004 में कुल 25360 खातो से कुल 2002915 (हजार) राशि वितरित की गयी।
4. वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र हेतु सबसे अधिक ऋण कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिया गया। इसके पश्चात् स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर द्वारा तथा बैक ऑफ इण्डिया द्वारा दिया गया। इस प्रकार वर्ष 2005 में कुल 28356 खातो से कुल 3067907 (हजार) राशि वितरित की गयी।
5. वर्ष 2006 में कृषि क्षेत्र हेतु सबसे अधिक ऋण कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिया गया। इसके पश्चात् स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर द्वारा तथा भारतीय स्टैट बैंक द्वारा दिया गया। इस प्रकार वर्ष 2006 में कुल 34032 खातो से कुल 3293868 (हजार) ऋण राशि वितरित की गयी।

उपर्युक्त वर्षवार तुलनात्मक आकडो के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रतिवर्ष ऋणराशि में वृद्वि की गई है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के विकास मे बैको की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सुझाव

1. कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आपकी बैंक आपके द्वार योजना की तरह प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाये जिसमें बैक ऋण संबंधी योजना की जानकारी दी जावे।
2. कृषि ऋण प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो।
3. कृषि के अलावा अन्य उद्योग–धंधों जैसे मूर्गीपालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन आदि व्यवसायों की स्थापना के लिये बैकों से अधिक मात्रा में ऋण की व्यवस्था की जाये ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों को अपना स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
4. ऋण स्वीकृति वितरण एवं वसूली की प्रक्रिया सरल हो।
5. ऋण लेने की प्रवृति में वृद्वि करने के लिये नियमित ऋण का भुगतान करने वाले कृषकों को पुरस्कृत किया जाये।
6. कृषि साख की पूर्ति आवश्यकतानुसार की जाये।
7. शासन की समस्त योजनाओं को ग्रामीण तक पहुँचाने के हर संभवतः प्रयास कर लोगो को योजनाओं से लाभान्वित किया जाये।

निष्कर्ष

निसंदेह यह कहा जा सकता है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण आदिवासियों के मुख्य व्यवसाय कृषि के विकास को सुनिश्चित तौर पर गति प्रदान करने तथा सिंचाई सुविधाओं का तीव्रतर विस्तार में सहायता मिलेगी जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक विकास होगा और भारत में विकराल रूप धारण कर चुकी खाद्यान्न संकट से उभरने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार भारत देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर देशवासियों के लिये खाद्य सुरक्षा एवं भुखमुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *बैंक ऑफ इण्डिया जिला अग्रणी बैंक जिला बडवानी*
2. *वार्षिक साख योजना वर्ष 2002–03*
3. *वार्षिक साख योजना वर्ष 2003–04*
4. *वार्षिक साख योजना वर्ष 2004–05*
5. *प्रतियोगिता दर्पण।*
6. *www.agriculture.mp.nic.in*
7. *www.agrimachinary.gov.in*